भारतीय मजदूर संघ
BHARATIYA MAZDOR SANGH

Resolutions
प्रस्ताव

राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-११००५५
दूरभाष : २३५८४२१२, २३५६२६५४, फैक्सः ९१-११-२३५८२६४८
RAM NARESH BHAWAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI-110055
TEL : 23584212, 23562654, FAX : 91-11-23582648 E-mail : bms@india.com

प्रस्ताव–1

दि 3/4/5 अप्रैल 2005 को दिल्ली में संपन्न भारतीय मजदूर संघ के चौदहवें अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन मे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है कि : –

विश्व श्रमिक समुदाय के विभिन्न श्रम संगठनों, परिषदों व महासंघों के इस अभिमत से हम सहमत हैं कि नवम्बर 2005 के माह में विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण विरोध दिवस उसी प्रकार मनाया जाना चाहिए जैसे कि 5 नवम्बर 2001 को मनाया गया था।

यह सभा इस विचार को भी स्वीकार करती है कि संसार के अर्धविकसित व अविकसित देशों के एक अरब लोगों को बढिया जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये जायें।

यह सभा पुनः दोहराती है कि विश्व व्यापार संगठन के ढांचे का लोकतांत्रीकरन करते हुए इसके एजेंडा में इस बात को प्राथमिकता मिले कि विश्व व्यापार लाभ का बराबर लाभांश सभी को प्राप्त हो। गत एक दशक के निरन्तर प्रयासों के बावजूद अभी तक इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

अब जबकि विश्व व्यापार संगठन की अगली मंत्री स्तरीय बैठक 13 दिसम्बर 2005 से सम्पन्न होगी वहीं केन्द्र में नव निर्वाचित सरकार की इस संबध में कार्यवाही निराशाजनक है। जुलाई 04 मे विश्व व्यापार संगठन की मध्य कालीन समीक्षा बैठक जिनेवा में भारत सरकार के प्रतिनिधि स्थिति की जटिलता को समझने और भारतीय व्यापार व अन्य राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने में विफल हुए हैं। इस के परिणामस्वरूप भ्रष्ट अधिकारीयों की चालें सफल हो जाती हैं और स्थिति पर उनकी पकड़ और दृढ़ हो जाती है।

अतः यह सभा सभी भारतीय नागरिकों को सावधान करना चाहती है कि चौकसी रखें ताकि धोखे और कायरता के इतिहास की पुनरावृति न हो।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह सभा निम्नलिखित घटनाओं की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है:–

- सन 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था किन्तु इस वायदे को तोड़ दिया गया और भारत ने पलटी खाते हुए मराकेश के गैट संधि पर हस्ताक्षर किए।

- यही कहानी द्वितीय मंत्री स्तरीय विश्व व्यापार संगठन के 1996 सिंगापुर बैठक में दोहराई गई जब कि बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा को प्रधानमंत्री आश्वस्त करते रहे कि इस प्रकार की (भारतीय हितों के विरूद्ध) किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे किन्तु अगले ही दिन संधीपर हस्ताक्षर कर दिए गए। तत्पश्चात परिणामस्वरूप इससे उपजी समय बद्ध आपूर्ति में भारत को आज तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ताजा उदाहरण यह है कि केन्द्र में वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जिस शीघ्रता पूर्वक पेटेंट अध्यादेश जारी किया वह सरकार की नीयत को दर्शाता है।

- इसके विपरीत तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन ने दोहा चतुर्थ मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय अभिप्राय को दृढ़ता से रखा और फलस्वरूप सभी विकासशील देशो के मंत्रियों का साहस बढा और एक मंच निर्माण की योजना बनी।

- परिणामतः भारत सरकार ने "जी–7" देशों को पत्र लिखकर अपने निश्चय से अवगत किया।

- इसके परिणाम का एक प्रभाव यह हुआ कि 'सार्क' देशों की बैठक मे विकासशील देशों की आवाज को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और भी प्रभावी ढंग से रखने का विचार बना।

- तदन्तर पंचम मंत्री स्तरीय इतिहासिक विश्व व्यापार संगठन बैठक में विकासशील देशों के मोर्चे ने सिंगापुर संधि को ही पुनर्विचार के लिए केवल मात्र एजेंडा बिन्दु बनाने का पुरजोर आग्रह किया और इसके लिए जी–21 देशों का मंच बनाया।

- किन्तु मध्यवर्ती समीक्षा बैठक जिनेवा में अब पुनः भारत ने जिस दृढ स्थिति को प्राप्त किया था उसे एक बार फिर गंवा दिया हैं और अमीर देशों सामने घुटने टेक दिये हैं।

- इस लिए भारतीय मजदूर संघ के इस चौदहवें अधिवेशन के अवसर पर स्थिति की गंभीरता और भयावहता के दृष्टिगत इस प्रश्न से जूझना पड रहा है कि क्या हम पुनः सफल होंगे ?
- इस पृष्ठभूमि के चलते हम पुरजोर अपील करते हैं कि : –
- ए एफ सी आई ओ, ए सी एफ टी यू, आई सी एस टी यू, डब्ल्यू एफ टी यू और उन समस्त परिषदों, महासंघों व विभिन्न देशों में कार्यरत संगठन संगठित होकर विकासशील देशों के करोडों निर्धनों को बचाने के पुनीत कार्य के लिए आगे आयें। शानदार जीवन जीने का एक अवसर उन्हें भी मिले। अतः 9 नवम्बर 2001 के प्रदर्शन समय जिस एकता का प्रगटीकरण हुआ था उसे दोहराया जाय।
- केन्द्रीय श्रम संघ और हजारों हजार अन्य श्रमिक जो कि प्रदेश स्तर पंजीकृत यूनियनों में सक्रिय हैं और अन्य लाखों कामगार व किसान आगे आयें।
- लाखों लाख बेरोजगारों की सेना आगे आये, और सभी मिलकर एक हो और अपना बचाव करें।

यह सभा दृढनिश्चय ये यह प्रस्ताव पारित करती है कि हम अमीर देशों के शोषण परस्त और विकासशील देशों विशेषकर भारत के हितों के विरुद्ध उनकी षडयंत्र कारी चालों को सफल नहीं होने देंगे।

भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि वह विकासशील देशों की ओर से इस विषय को उठाये और जो है उसे स्वीकार करो अथवा चलते बनो केवल यही विकल्प अगर हाँगकाँग की **WTO** में भी परिषद मे बचता है तो विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल आने का मार्ग प्रशस्त करें।

भारत सरकार के उपरोक्त प्रयास में हमारा पूर्ण सहयोग और समर्थन रहेगा किन्तु दूसरी सूरत में देश व्यापी आंदोलन के लिए हम विवश होंगे।

यह सभा देश भर के सक्रिय करोड़ों कार्यकर्ताओं से आग्रह करती है कि :

- देश के प्रत्येक जिला, तहसील, नगर व गांव में वर्षा ऋतु के पूर्व और इस

अधिवेशन के तुरंत पश्चात श्रमिकों, किसानों को संगठित करते हुए उपरोक्त के संदर्भ में जन जागरण के कार्यक्रम करे।

- प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन, धरना, रैली, रोड शो कर पखवाड़ा 17 सितम्बर राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से 2 अक्टूबर 2005 गांधी जयन्ती तक मनायें।
- 'सरकार झुकाओ देश बचाओ' नाम से नई दिल्ली संसद भवन के सम्मुख राष्ट्रीय स्तर पर विराट धरना दिसम्बर 2005 मे आयोजित किया जाये।

प्रस्तावक :..... अनुमोदक

प्रस्ताव—2

सीधे विदेशी निवेश की संकल्पना व क्रियान्वयन को आमान्य करो

भारतीय मजदूर संघ का चौदहवां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 3–4–5 अप्रैल 05 रामलीला मैदान नई दिल्ली में इस प्रस्ताव द्वारा सीधे विदेशी निवेश की धारणा व इसे प्रवेश की अनुमति दिए जाने का सर्व सम्मत् व सर्व समर्थित विरोध करता है।

इस सभा का अभिमत है कि विदेशी निवेश विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बजाय विश्व भर में विकासशील देशों के समृद्ध प्राकृतिक व अन्य संसाधनों से लाभ उठाने को सोचने का कार्य कर रहा है। निश्चित् लाभंश, टैक्स छूट, भारी रायल्टी व कानूनों का उल्लंघन करके निवेशित् देशों की विवशता का लाभ उढाया जाता है। राजनेता व भ्रष्ट नौकर शाह अपने क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति हेतु किस प्रकार स्वराष्ट्र के हितों की सौदेबाजी करते हैं यह जग जाहिर है। यह बात भी जग जाहिर है कि किस प्रकार विदेशी निवेश घरलू शेयर बाजार को उछालते व छोटे उद्यमियों को पछाड़ते और कभी

कमी निवेशित् देशों की स्थिर अर्थ व्यवस्था को झिझोड़ते हैं। यह सभा मत् कुछ वर्षों में इस संदर्भ में अर्जेनटीन, ब्राजील, मैक्सिको, ईण्डोनेसिया, मलेशिया एवं कोरिया जैसे देशों का जो हाल हुआ है उस से अवगत है।

यह सभा घरेलू स्थिति से भी अवगत है जहा आर्थिक सुधारों के प्रथम चरण और विशेषकर उर्जा क्षेत्र में एनरान और वैकेटल तथा सटेरेलाईट व हिल जिन्होंने बाल्को व मार्डन फूड को खरीद कर शोषण से हट कर कोई भिन्न तस्वीर प्रस्तुत नहीं की। जिन्होंने आई टी डी सी होटल समूह को खरीदा उन्होंने भी श्रमिकों का जम कर शोषण किया। इस सब के पीछे महानगरों के मध्य स्थित इन होटलों अथवा मार्डन फूड जैसी कम्पनियों के भवनों के साथ अवस्थित जमीन की खरीददारी की व्यवसायिक मनोवृत्ति कार्य रत थी और उद्योग बढ़ावा केवल मुखोटा मात्र था।

सन् 1996 में विनिवेश आयोग स्थापना का उदेश्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की विनिवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ इन्हें मजबूती प्रदान करना था किन्तु 2001 आते आते इस के स्थान पर विनिवश मंत्रालय का गठन केन्द्र सरकार द्वारा कर दिया गया। इस मंत्रालय का काम केवलमात्र प्रतिष्ठानों को बेचने का हो गया। यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि कौन प्रतिष्ठान लाभ दे रहा है अथवा राष्ट्रीय दृष्टीकोण से उस का क्या महत्व है और खरीददार कौन है।

आटो मोबिल बाजार की चमकती मारूति उद्योगिक ईकाई, लाभ कारक नैल्को, पैसा कमाऊ तेल क्षेत्र की कम्पनियां आदि वह औद्योगिक ईकाईयां हैं जिन्हे विनिवेश सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया।

वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिया कि वह इस प्रक्रिया को बंद कर देगी और किसी लाभ प्रद प्रतिष्ठान का विनिवेश नहीं किया जाएगा किन्तु सत्ता संभालने के अगले ही दिन दिल्ली व मुम्बई हवाई अड्डों को विनिवेशित कर दिया गया। यह हवाई अड्डे सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत एयर पोर्ट अथारिटी इन ईन्डिया के अधीन कार्यरत थे। यू पी ए सरकार अब गुपचुप संवेदनशील प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग का निजीकरण करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। राष्ट्रीय जनतन्त्र गठबन्धन सरकार के समय इस पर रोक लगी थी। केलकर समिति

रिपोर्ट इसी विषय से सवंधित है। कोल फील्ड का निजीकरण भी चर्चा में है। ईलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के कारण इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के द्वार निजीकरण के लिए खुल गए हैं। इस क्रम में नवरत्नों में शुमार बी एच ई एल के निजीकरण की भी शीघ्र बारी आने वाली है।

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् भामस की यह सभा इस निष्कर्ष पर पंहुची है कि यह देश को वेचने के सिवाय और कुछ नहीं है।

यह सभा इस सबंध में प्रस्तुत किए जा रहे तर्को व दलीलों को समझने में असमर्थ है। इस सभा की यह मान्यता ओर पक्की राय है कि :–

- लाभ प्रद सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो तर्कयुक्त गत तीन वर्षों में 15 प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं और उसी अवधि के एक वर्ष 2002 में 52100 करोड़ का टैक्स पैदा कर रहे हैं और विगत के घाटों का 13000 करोड़ के नुक्सान का बोझ भी उठा रहे हैं उस स्थिति में उपरोक्त को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रुप में देखा जाना चाहिए विशेषकर जब विश्व में वाजार की स्थिति कमजोर हो रही हो और विश्व अर्थ व्यवस्था चरमरा रही हो। ऐसी सूरत में सुधार की गति को दृढ़ता प्रदान की जानी चाहिए।
- इस लिए सार्वजनिक क्षेत्र में राजनेताओं नौकरशाहों की दखलन्दाजी बन्द होनी चाहिए।
- किसी लाभकारी सार्वजानिक प्रतिष्ठान जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े उत्पादन या सेवा कार्य से संवंधित है उसे किसी विदेशी के हाथों बेचने के कार्य को हम राष्ट्र की सर्वभौमिकता व स्वाभिमान के साथ समझौता मानते हैं।
- निवेश करने के लिए देश में धन की कमी नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अच्छी संभावानाओं के अभाव में डेढ़ लाख करोड़ की धन राशि पड़ी है। इसी प्रकार कमाऊ भारतीय जीवन बीमा के पास एक लाख करोड़ की अतिरिक्त धन राशि रखी हुई है जिन्हें अच्छे क्षेत्र जहाँ निवेश किया जा सके की तलाश है। लघु बचत स्कीम से सरकार प्रतिवर्ष 4.60 लाख करोड़ धन राशि अर्जित करती है। जिस पर भी अगर संस्कार को और धन की आवश्यकता है तो वह देश हित में जनता से अपील करे तो देश भक्त जनता सरकार को जितनी राशि चाहिए उतनी उपलब्ध करा सकती है।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि अर्थ व्यवस्था में बचत को मजबूत आधार बनाया जाए। इस लिए घरेलू बचत दर 26 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए।
- इस संबंध में सरकार की आर्थिक समीक्षा तथा विशेषज्ञों के राय कि घरेलू बचत को हतोत्साहित करने के लिए निवेश पर टैक्स सुविधा को घटाने का कार्य जैसा कि को लेकर समिति सिफारिशों से प्रकट होता है गरीब विरोधी है।
- यह सभा देश के योजनाकारों की इस राय से हैरान है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002– 2007 मे रेवेन्यू घाटे की पूर्ति सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को विदेशी पूंजीशाहों को बेच कर की जा सकती है। अतः 500 शीर्ष विदेशी धन कुबेरो के द्वार खटखटाए जाये और आमंत्रण दिया जाये कि वे भारत में निवेश करें। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8 अरब अमरीकी डालर का कोष बनाया जा सकेगा। साथ ही साथ देशी निवेशकों को हतोत्साहित व घरेलू वस्तुओं पर ध्यान देने के बजाय उपभोक्ता रूझान को बढाकर बाजार की मांग बढायी जाय। यह योजना अगर कार्यान्वित होती है तो भविष्य अंधकारमय होगा यह सभा स्पष्ट रूप से देश रही है कि देश के उत्पादन के धुरे को विदेशी निवेशक अपनी ओर मोडने में सफल हो रहे हैं। प्रयास यह हो रहा है कि भारत में भारतीय हितों को फांसी पर लटका कर विदेशियों के लिए स्वर्ग की रचना की जाये।
- यह सभा इस बात पर भी चिंतित है कि सरकार इस बारे में भी असफल रही है कि भूमण्डलीकरण की दौर में किस स्तर पर कितनी और किस प्रकार की तकनीक की दरकार है इस कारण से बडी मात्रा में बेरोजगारी को स्थान मिला है कोई भी विदेशी उपभोक्ता वस्तु जब देशी बाजार में लायी जाती है तो उसके साथ उन्नत तकनीक के कारण देशी बाजार में उसी प्रकार की स्वदेशी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। फलस्वरूप देशी उत्पादन कर्ता भी वैसी ही तकनीक को अपनाने का प्रयास करता है। जिसके कारण रोजगार प्रभावित होता है छिन जाता है। इस अंधी दौड़ में समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि इससे असमानता बेरोजगारी में बढोत्तरी, शहरीकरण, प्रदूषण, जल पूर्ति का अभाव आदि समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सरकार की भूमिका यहां समाप्त हो जाती है। और

वह इस आर्थिक परिदृश्य को मूक दर्शक की भांति देखती रहती है। यह सभा मगर इस दृश्य को चुपचाप सहन नहीं कर सकती और यह निश्चय करती है कि भारत बेचने की इस साजिश का पुरजोर तरीके से प्रतिकार किया जायेगा।

- यह सभा निश्चित मत व्यक्त करती है कि विदेशी तकनीक युक्त विदेशी निवेश भारतीय जनों के अनुरूप नहीं है। विगत दशक की योजना जिसमें योजनाकारों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनके निर्देशों का पालन किया। किन्तु यथार्थ यह है कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। जब तक विदेशी तकनीक के आक्रमण से बचा नही जाता अथवा वह हमारे हितों के अनुकूल उपलब्ध नहीं होती या जब तक देश इसे स्वीकारने की तत्परता नहीं दिखाता तब तक किसी भी रोजगार सृजन योजना को कार्यरूप देना निरर्थक ही होगा।
- पूर्व राजग सरकार असफल रही है और रोजगार सृजन के मोर्चे पर यूपीए सरकार भी असफल रहने वाली है। रोजगार गारण्टी प्रारम्भ से ही भ्रम मूलक है। ग्रामीण लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है किन्तु ऐसा दिखाई देता है कि यह कोरा आश्वासन ही सिद्ध होगा और बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो पायेगा। एक ओर शहरी बेरोजगारों को दुर्लक्ष्य किया गया है तो दूसरी ओर इसी गारण्टी अधिनियम में समाज को काम के बदले अन्न लाभ प्राप्त करने की राह दिखाई गयी है। यह सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जब तक सही समय स्थान पर प्रकल्प स्थापित नहीं किये जाते और कुछ विशेषताओं की व्याख्या नही की जाती तब तक यह सारा प्रयास व्यर्थ ही जायेगा। क्योंकि केन्द्र या प्रदेश सरकार इस बारे में सजग नहीं है और प्रयास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता परिलक्षित नहीं हो रही अतः जैसे भूतकाल में यह प्रयास असफल हुए उसी प्रकार अब भी होंगे।
- अतः स्थिति का समग्र अवलोकन करते हुए यह सभा भारत सरकार के नीति निर्धारकों से मांग करती है कि :
- सीधे विदेशी निवेश को थ्योरी और प्रैक्टिस सभी रूप में बंद करें।
- दूर संचार व एयरपोर्ट में प्रस्तावित 74 प्रतिशत तक निवेश में बढोत्तरी को निरस्त किया जाये।

- एक त्रिपक्षीय निवेश आयोग का गठन किया जाये जिसमें श्रमिकों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाये।
- उपरोक्त आयोग के सम्मुख घाटे वाले प्रतिष्ठानों के केस एक एक कर के प्रस्तुत किये जायें जिससे कि उन्हें लाभप्रद स्थिति में लाने और चलाने के सार्थक प्रयास किये जा सकें।
- तकनीकी नीति का देश के लिए प्रावधान किया जाये और इसके लिए सुविज्ञ अर्थ शास्त्रियों से परामर्श लिया जाये।
- इस बात की स्पष्ट व संशय रहित घोषणा की जाये कि लाभप्रद सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का विनिवेश नहीं होगा।

प्रस्तावक :..... अनुमोदक :.....

प्रस्ताव–3

भारतीय मजदूर संघ के चौदहवे त्रैवार्षिक अधिवेशन का यह विचार है कि बेरोजगारी और निर्धनता दो ऐसे रोग हैं जिन के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तथा राष्ट्र को ग्रहण लगा हुआ है। गत् पांच दशक में सभी सरकारों के एजेन्डा पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शीर्ष पर रहा है किन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि इस ओर सरकारों ने ईमानदारी से कतई कोई प्रयास नहीं किए। भारत सरकार ने स्पष्टतया जुलाई 2001 में उदारीकरण, निजिकरण व भूमण्डलीकरण तथा विनिवेश नीति की विश्व बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्देश पर घोषणा की। भारत सरकार ने नयी आर्थिक व उदारीकरण नीति की भी व्याख्या की और इस नीति के फलस्वरुप एक सुनहरे भविष्य की सुन्दर तस्वीर देश के सामने पस्तुत की। हम स्मरण करवाना चाहेंगे कि इस नीति पर भामस ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार को आवहान दिया था कि इस नीति पर सूत्रवद्ध रुप में चर्चा करवाए किन्तु सरकार ने अपनी घोषित नीति में परिवर्तन की आवश्यकता नही समझी। मौंटेक सिंह आहलूवालिया

समिति की रोजगार के अवसर रिपोर्ट, गीता कृष्ण समिति की व्यय सुधार रिपोर्ट, राकेश मोहन समिति के निजीकरण सम्बंधी रिपोर्ट तथा योजना आयोग उपसमिति की रोजगार सृजन व विदेशी निवेश पर विशेषज्ञों की राय आदि सब ने सरकार के नजरिये को सही ठहराया और बताया कि उपरोक्त नीति के कारण अर्थ व्यवस्था सुधरेगी, रोजगार बढेगा एवं औद्योगिक मोर्चे पर गतिविधि तेज होगी। उत्पादन बढेगा और श्रमिकों व आम आदमी की आमदन भी बढेगी। वस्तुओं की मांग बढेगी और उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था चमक उठेगी।

- यह सभा महसूस करती है उपरोक्त घोषणाओं आश्वसनों के विपरीत विगत चौदह वर्षों में अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है। संगठित क्षेत्र में रोजगार घटे हैं। छंटनी तालाबंदी, कारखाना बंदी के कारण लाखों लाख श्रमिकों का रोजगार छूट गया है। आर्थिक सुधार इस नीति के फलस्वरूप स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना, स्थानानन्तरण व ठेकेदारी प्रथा को बढावा मिला है। औद्योगिक प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा के चलते नियोजकों ने नयी तकनीक को अपनाना प्रारम्भ किया है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक बल में घटा है। सरकारी, अर्धसरकारी व सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के रोजगार तो जैसे बंद ही हो गये है। यह कुचक्र कुछ ऐसा चला कि "रोजगार नहीं आमदन नही–न्यूनतम मांग– न्यूनतम उत्पादन"। कारखाना बंदी के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था एवं सामान्य नागरिक तथा श्रमिकों को जबरदस्त धक्का लगा है। यूपीए की केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम का विधेयक संसद में रखा है। किन्तु इसके परिणाम अपेक्षानुरूप होंगे इसकी क्या गारण्टी है। इसमें शहरी बेरोजगारों तथा महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं है। इस स्कीम के कियान्वयन पर भारी धन राशि के संबंध में सरकार ने कोई ब्यौरा नही दिया है।

- यह सभा बताना चाहती है कि उपरोक्त आर्थिक नीति के कारण 1983 से 2000 अवधि में रोजगार विकास दर में प्रति वर्ष 2.27 प्रतिशत गिरावट आयी है। सेंट्रल स्टैटिक्स सेल के अनुसार संगठित क्षेत्र के रोजगार में प्रतिवर्ष 0.08 प्रतिशत की गिरावट आयी है। 1993–94 में 273.75 लाख से 2001–2002 में 272.06 लाख रह गये हैं कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो सार्वजनिक, निजी, उत्पादन, निर्माण, वित्तीय, रियल स्टेट सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं।

- यह सभा अतः सुविचारित मत व्यक्त करती है कि वर्तमान आर्थिक नीति, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण व निजीकरण के चलते आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रही है और गत 14 वर्षों में इसकी हालत बद से बदतर हुई है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस नीति पर पुनर्विचार किया जाये। सभी आर्थिक संगठित पक्षों की गोल कान्फ्रेंस बुलाई जाये और अर्थ व्यवस्था का भारतीय परम्परा, सांस्कृतिक मूल्यों, और समाज की आवश्यकताओं आधारिकत माडल तैयार किया जाय। यह सभा आग्रह करती है कि आर्थिक सिस्टम इस प्रकार का विकसित किया जाये जिसमें समाज के प्रत्येक प्राणी का प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति हो। हम यह भी मांग करते हैं कि प्रत्येक बेरोजगार को काम का अधिकार दिया जाय। हम सभी श्रमिकों को आवाहन देते हैं कि वह प्रशिक्षण व जन जागरण अभियान चलायें जिससे कि काम के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और समाज का कल्याण हो सके।

प्रस्तावक :..... अनुमोदक :.....

प्रस्ताव—4

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये छठे वेतन आयोग का गठन

गत १२ जनवरी, 2005 को भारत सरकार के वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व सम्पन्न हुई मीटिंग सें भारतीय मजदूर संघ की ओर से 10वर्ष के अन्तराल के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये छठवें वेतन आयोग के गठन को अविलम्ब गठित करने की मांग उठायी गयी थी। पंचम वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर निम्न प्रकार से अनुशंसा की है।

अनुशंसा संख्या 171.72

" यदि किन्हीं कारणों से केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिये द्विपक्षीय वेतन समिति गठन करने में कठिनाई का अनुभव कर रही है तो

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये 10वर्ष में एक बार उनके वेतन मानों से संशोधन करना चाहिये। पंचम वेतन आयोग की अनुशंसाओं को। जनवरी,1996 से लागू किया गया था, तदानुसार षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसायें भी। जनवरी, 2006 से लागू की जानी चाहिये, वेतन आयोग का गठन भले ही कभी किया जाये। सरकार को यह भी विचार करना चाहिये कि वेतन आयोग को अपना कार्य सम्पादन करने में लगभग 3 वर्ष लगते है अतः अगले वेतन आयोग का गठन हर हालत में। जनवरी, 2003 को कर देना चाहिये, ताकि उसकी रिपोर्ट। जनवरी, 2006 को उपलब्ध हो सके।"

पंचम वेतन आयोग ने भी द्विपक्षीय वेतन समिति गठन के बारे में अनुशंसा की थी। यही धारणा प्रारम्भ से ही भारतीय मजदूर संघ की रही है, जिसे आज तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार पंचम वेतन आयोग ने भारतीय मजदूर संघ की मांग का समर्थन ही किया था। यदि केन्द्र सरकार किन्हीं कारणों से द्विपक्षीय वेतन निर्धारण समिति का गठन नहीं कर पाती है तो उसे तुरन्त छठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करना चाहिये, ताकि उसकी रिपोर्ट। जनवरी, 2006 तक प्रकाशित हो सके। अगले वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को गति देने हेतु यू० पी० ए० गवर्नमेन्ट को Common Min programme के अन्तर्गत किये गये अपने वादे के अनुसार प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन को करना चाहिये, जिससे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की रिपोर्ट। जनवरी, 2006 से लागू की जा सकें।

अतः भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्य समिति भारत सरकार से मांग करती है कि यदि वह द्विपक्षीय वेतन निर्धारण समिति का गठन नहीं कर सकता तो उसे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये छठवें वेतन आयोग का गठन शीघ्र करना चाहिये ताकि इसकी रिपोर्ट। जनवरी, 2006 तक प्रकाशित हो सके।

प्रस्तावक :..... **अनुमोदक :**.....

प्रस्ताव–5

नये पेटेंट कानून समाप्त करने की मॉग करता प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ के 14वें त्रैवार्षिक अधिवेशन की यह महासभा एकमत से यह मॉग करती है कि मार्च 2005 में पारित किये गये पेटेंट कानून को केन्द्र सरकार तुरन्त वापस ले, और ऐसा करने में विश्व व्यापार संघ की सदस्यता एवं पूर्व में किया समझौता अगर रोड़ा बनता है तो तुरन्त विश्व व्यापार संघ की सदस्यता का त्याग कर विकसनशील देशों का नया विश्व व्यापार संघ बनाने की पहल भारत सरकार करे ।

नया पेटेंट कानून विश्व स्तर के पेटेंट को 20 वर्ष के अवधी की मान्यता देगा, ऐसा ही कानून भारत में अंग्रेजों ने 1911 में बनाया था एवं वह 1970 तक चला था । उक्त काल में भारत में दवाईयॉ बेशुमार महंगी बेची जा रही थी । गरीबों की जरूरतों को देखकर भारत ने अपना पेटेंट कानून बनाया जिसके चलते विश्व बाजार के अनुपात में भारत में दवाईयॉ 10 प्रतिशत कीमत पर मिलती रही है ।

भारतीय कम्पनियों के पास 1 प्रतिशत पेटेंट केवल होने से दवाईयों का पैसा और दवा कंपनीयों का अरबों खरबों का मुनाफा विदेश में जाएगा । भारत की लूट होगी।

विदेशियों का यह एकाधिकार एवं लूट बीस बरसों तक चलेगी एवं बाद में भी नये किसी को पेटेंट मिलेगा यह असंभव है क्योंकि तब तक स्पर्धा में कोई नहीं बचेगा। इसके अलावा भारत की 26 हजार दवा कम्पनीयों में से 15 हजार तुरन्त बंद हो जाएगी ऐसा विशेषज्ञों का मानना है ।

दवाईयों की कीमतें बढ़ेगी तो खुदरा व्यापार करने वाली दूकानों में पूंजी लगाना मुश्किल हो जाएगा इसलिऐ बड़ी संख्या में दन दूकानों को बंद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा । ट्रिप्स समझौते के धारा 31 (बी) का उपयोग करके उत्पादन बेचने का एक सुनहरा अवसर भारत को उपलब्ध हो सकता था । किन्तु कानून में इस धारा में निहीत पेटेंट कन्ट्रोलर के अधिकारों को वह स्थान ही नहीं दिया गया है । जबकि कई देशों ने यह प्रावधान किया है ।

व्यापक जन स्वास्य एवं रास्ट्रीय उद्योगों से जुड़ें हुए कल्याणकारी प्रावधान इस कानून में रखने की चिन्ता नहीं हुई है ।

पहले कानून में पेटेंट पूर्व आपत्ति का प्रावधान था अब नये कानून में पेटेंट पश्चात आपत्ति का प्रावधान है यह बड़ा हास्यास्पद है ।

ऐसे कई बिन्दू देश के लिए घातक एवं गरीबों का जीवन नष्ट करने वाले तथा विदेशी पूजीपतियों के गूलाम बनाने वाले इस कानून में हैं । जिसकी यह महासभा घोर निन्दा करती है ।

अपनी ओछी राजनीति चलाने वाले वामपंथी दलों ने अपनी सहमति देकर गरीब जनता एवं मजदूरों का विश्वासघात किया है । देश के राजनेता नौकरशाह विदेशी दवा कंपनियों द्वारा खरीदे गये है इसलिये यह देशविघातक कानून पारित हो पाया है ।

इसलिए यह महासभा देश के करोड़ों गरीबों एवं श्रमिकों से आवाहन करती है कि यह जंग अब संसद के भरोसे न रहते हुए सड़क पर लड़ने केलिए तैयार रहें ।

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को यह महासभा आदेश देती है कि व्यापक जनसंपर्क एवं जनजागरण अभियान द्वारा जनता की आवाज को बूलंद करते हुये एवं श्रमिक और किसानें की एकता बनाते हुए भारत के भविष्य को विदेशी शिकंज से बचाने के लिये कृत संकल्प हो जाए ।

प्रस्तावक :..... अनुमोदक :.....

Draft Resolution-1

This 14th session of the triennial all India conference of BMS held between 3rd-5th April 2005 at New-Delhi resolves unanimously,

AND CONCURS: with the world opinion of the workers belonging to various trade unions, councils and federations to hold in the month of Nov'05 a worldwide "ANTI-GLOBALISATION DAY", as was observed on 9-11-01.

THIS CONFERENCE FURTHER ENDORSES: the view expressed by the organized labour to strive and ensure that the developing and under-developed third world gets a due share of the prosperity, render the unemployed youth, the decent jobs, and provide one billon people world over a chance to live a decent life.

THIS CONFERENCE FURTHER REITERATES: the need to re-shape the structure and 'in-built' agenda of WTO, and evolve a mechanism that may democratically decide and endow an equitable share of the benefit of the world trade to all, noting interestingly that despite over decade's efforts this world body has failed miserably to do it.

While the next ministerial meet of WTO is slated to be held on and from 13th of December' 05, the dismal performance of the newly elected Govt. at center during the mid-review round of July'04 held at Geneva on one hand has exposed the Govt.'s lack of understanding of the complex situation and inability to protect India's trade interest, while on the other hand the exploiting lobby of corrupt bureaucrats are encouraged by this, and seem to gain foothold again.

HENCE THIS CONFERENCE CAUTIONS: the Indian citizen to keep a vigil since this is the time that may repeat the history of treachery and cowardice.

THIS CONFERENCE COMPREHENDS THE FOLLOWING EVENTS.

- In 1989 while the then premier made a clear promise, it was vindicated and India took a summersault and signed the GATT treaty at Marrakech.
- The second WTO ministerial meet held in 1996 at Singapore also witnessed such an act being repeated, for Indian delegation took the same 'U' turn and signed the treaty despite the fact that the then Premier kept promising the parliament till just a day before that no such treaty would be signed. India faced severely in meeting the lime lable of compliance on account of this commitment since then. The current haste in which the UPA Govt., issued the ordinance amending the patent law is glaring example.
- The commerce minister then Late Mr.Maran kept his foot down firmly and negotiated the round number four at Doha courageously, which provided the foothold for the developing nations to gather courage and bring about a formation.
- The Govt. of India sent the letter subsequently to the 'G-7' countries explaining the stand taken.
- Subsequent meetings of SAARC countries creating a strong international voice for the developing countries.
- The historic fifth WTO meet on ministerial level, where the broadside by the developing nation members insisting upon making the 'Singapore issues' only to be the agenda to be sorted out first, culminated into formation of the group called 'G-21'.
- The midterm meet of WTO at Geneva, where the minister and the delegation all bungled again, losing ground to the rich nations despite the promise of holding situation firmly.
- This fourteenth all India conference of BMS after having taken a close look at this critically balanced situation

enveloped by the bleak prospects, spelling a disaster should we fail again.

- THIS CONFERENCE ON THIS BACKDROP APPEALS:
- AFL-CIO, ACFTU, ICFTU, WFTU AND ALL THOSE COUNCILS/ FEDERATIONS WORKING ON THEIR NATIONAL LEVEL TO UNITE TO SAVE THE BILLION STARVING POOR OF THE DEVELOPING COUNTRIES. HAVE THEM A CHANCE TO LEAD DECENT LIFE. REHERSE THE EXHIBITION OF UNITY DEMONSTRATED ON 9th NOV.'01.
- THE CENTRAL TRADE UNIONS AND THOSE THOUSAND OTHERS SERVING THIS COUNTRY THROUGH THEIR REGISTERED UNIONS AND STATE LEVEL UNIONS.
- THE MILLIONS OF WORKERS AND MILLIONS OF KIASANS OF INDIA.
- THE EVER MOUNTING ARMY OF UNEMPLOYED YOUTH OF INDIA.

to join hands for solidarity and for survival.

This conference resolves determinedly to oppose the sinister designs of the exploitative rich countries to smother the interests of the developing countries in general and those of India in particular.

This conference implores the govt. of India in general and the Premier in particular to take on this cause of developing nations personally and walk out of the WTO meet, should the Hongcong meet offer only the 'take-it-or-leave-it' alternative.

The conference offers the Govt. of India unequivocal support in this endeavor, but also warns a nation wide stir otherwise.

This conference of BMS appeals the millions of activists across the country:

- To organize villege/Tahasil/district level joint pre-monsoon programmes of mass awakening of workers and kisans immediately after this conference.
- To organize the state level fortnight programme of demonstrations, rallies, dharnas, and road shows etc., between Saturday the 17th September 2005(Vishwakarma Jayanti, our national labour day) and Sunday the 2nd October 2005(Gandhi Jayanthi).
- To organize 'Sarkar jhukao-Desh bachao' mass dharna in 'New Delhi' on parliament on Monday the 12th December 2005.

PROPOSED BY: SECONDED BY:

Draft Resolution-2

REJECT THEORY AND APPLICATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

This session of the 14th triennial conference of BMS being held during 3rd- 5th April 2005, at Ramleela Maidan, New Delhi, resolves unanimously to oppose the Foreign Direct Investment, in theory and practice.

This conference observes that FDI rather than becoming instrument of development has become symbol worldwide for siphoning away riches of the developing economies. The guaranteed percentage of profits, tax holidays, and hefty royalties, over invoicing and under invoicing, coercions and lawbreaking are some such means of squeezing the helpless recipient countries. The politicians and bureaucrats are known world over for trading-off the nation's interests for a small piece of personal gains. The FDIs are known to swing the domestic stock markets, swindle the small investors, and at times are

known to dabble with the stability of the economies of the recipient country.

This conference has taken note of the events during past few years in this context in Argentina, Brazil, Mexico, Indonesia, Malaysia and Korea.

This conference has also kept a close track on the happenings on the domestic front. The players in the first phase of these reforms in general and those in the power sector like ENRON AND BECHETL in particular, The STERLITE and HLL who bought up BALCO and MODERN FOOD respectively did not portray different picture. Those who bought the ITDC hotels minted money and exploited workforce to the hilt like all others. The scheme of things looks more a scandal of land grabbing than the one intending to improve health of that industry.

The Conference observes that the purpose of the disinvestments commission, at the time of its formation around 1996 was stated to be to strengthen the PSEs by using the disinvestments proceeds. This disappeared within no time and in 2001 the central Govt., established disinvestments ministry. The emphasis was by now to sale the PSEs, and preferably to the strategic partners lock-stock-barrel, no matter if any of them was loss making or profit making. All and sundry in the Government thought that the prospect better be a foreigner.

The sterling performer in automobile market-MARUTI; the profit making-NALCO; the money minting oil companies are the units which have been found favorites on the disinvestments list. The current Govt., in saddle at the center, UPA GOVT., did promise the whole nation that the Govt., would stop this process and would not disinvest the profit making PSEs. Within no time of the Govt., assuming the power announced the disinvestments of the Airports of 'Delhi' and of 'Mumbai', at present working under the 'Airport authority in India'. At present this UPA Govt., is discussing, though not openly, to divest the strategic defense production to the private players. This process was totally

halted in the regime of NDA Govt. The Kelkar report is all about it. The transfer of the coalfield to private partners is very much in the pipeline. The Electricity Act 2003 has opened the flood -gates for private sector into this crucial field. The next to go are some navratnas like BHEL.

Having taken into consideration these glaring examples, this 14th conference of BMS is of the firm opinion that this is nothing else but sale of nation.

This Conference is unable to buy the reason and the logic being advanced by the Government and their experts.

- THIS CONFERENCE IS OF THE FIRM CONVICTION AND OPINION:

- That the profit making PSEs, while have been earning reasonable profits, (15% avg., for past 3 years) and at the same time generating taxes to the tune of Rupees 52100 crore (2002)and also have carried the burden of losses of around Rs.13,000/- crores incurred by the siblings. This must be seen as historic achievement especially in the era of falling markets and dwindling economies world over. This trend of the recovery must be strengthened.

- That the policies of political / bureaucratic interventions in PSEs should be done away with.

- That the sale of the profit making unit of PSE, engaged in the manufacturing /services, in the essential, strategically important activity or is engaged in the core activity, to any strategic partner, particularly foreigner, is a compromise with the country's sovereignty and self-respect.

- That there is no shortage of the funds in India for investment purpose. The nationalised banks claim to have with them lying idle a fund of Rs.1.50 lac crore, for want of good prospect. While the giant money mopper of India, the LIC OF INDIA is reported to have huge surplus of

Rs. 1/-lac crore, searching for good prospect. The small saving schemes are enabling the Govt., to collect around Rs. 4.60 lac crore every year. If ever Govt., needed more money from the people of India, an appeal made to their patriotism, would certainly fetch India, more money, as and if needed.

- That the target of growth rate @ 8%p.a. during 10th five year plan is achievable provided economy provides a strong saving base. Thus the domestic saving must go up from the current rate of 26% to around 32% p.a.

- That the economic propositions of the central Govt., and their experts in discouraging the domestic savings by withdrawing the tax benefits in investment, as has been demonstrated by the KELKAR COMMITTEE RECOMMENDATIONS, are callous and patently anti poor policies.

- The Conference is perplexed at the propositions of the planners of our country to take the growth path during 10th plan (2002-2007) to fill the shortfall in the revenue generation by selling the PSEs to foreign money-lords. The plan is to tap these strategic partners by inviting the top 500 foreign barons and making a fervent appeal for investment by knocking at their Boardrooms. This speculative fund mopping attempt makes basis for the target collection of US b$ 8/- every year under this plan. Simultaneously by neglecting and discouraging Indian common investor, the planners want the domestic saving to go for consumption and expect creation of the consumption demand. This conference considers this road map for future to be suicidal. The conference clearly foresees that engine of production of India is systematically being weaned away by the foreign players. The attempt is to create a paradise for foreigners by hanging Indian interests up.

- This conference observes from the close quarters the utter failure of the Government in monitoring and defining the

acceptable levels of technology during the era of globalisation. This has paved way for large-scale unemployment. Every entry of foreign product, unless meant to be sold totally in the foreign markets, brings in automatically the upgraded levels of their technology in this controversy, changing the domestic equations of using it. As a chain reaction, the domestic producers adopt all those levels, which are man replacing and essentially the job-eaters. In this mad race the society has paid heavy price-the increased levels of disparity, high levels of unemployment, evils of urbanisation, pollutions, water contamination etc. etc. The government's role of monitor has vanished and government remains a mute spectator to this unfurling economic scenario. This conference cannot take this lying low and is resolved to retaliate this in big way and 'save India from the sale'.

- This conference is of strong opinion that this foreign direct investment backed by foreign technology does not suit India's requirements. The last decade of Indian planning which did follow the dictates of foreign money lending nations/institutions in totality, have failed squarely in creating the employment opportunity. Unless the invasion of the technology is either monitored to suit our needs or is halted till the nation is prepared, it would be paradoxical to plan for employment generation schemes.

- The NDA Govt. has failed and so also the UPA Govt., would experience the same fate on front of employment generation. The controversial enactment does provide the opportunity for the rural masses to opt for the employment under this scheme. However after having taken analytical view of the scheme of things, the conference perceives that this is nothing but a sop and at the end would not yield any solution on the front of employment problem. On one hand the enactment does overlook the urban unemployed youth, while on the other hand, the scheme is no guarantee, to enable the society to procure the perpetual gains as sequel

to the work done on these 'guarantee works'. The conference observes that unless the proper projects are located and some benchmarks are defined any attempt to bring this in to play only would mean 'resource guzzling'. As there is no apparent move either from the central/state governments in this direction, therefore evidently, this scheme only would meet the same fate, as of others, did in the past.

- Taking the holistic view of the situation prevalent in the economic front, this 14th all India conference demands of the Govt., and the policy makers
- To reject the FDI in theory and practice.
- Withdraw the proposed hike of 74% cap in telecom and airports forthwith.
- Create the inv-estment commission of tri-partite nature with labour securing equal representation.
- Take up case by case the loss making PSEs, before the said commission so as to find the measures of strengthening PSEs and make them viable.
- Create 'Technological Policy" for the country by taking in to consultations from the sections f the society who have economic concerns.
- Announce in unequivocal and clear terms that profit-making PSE would not be provatised.

PROPOSED BY: SECONDED BY:

Draft Resolution-3

Unemployment

This 14th National Triennial Conference of BMS at New Delhi on 4th April 05 notes that the unemployment and poverty are the two main ills afflicting the National economy & the Nation. In the last five decades the employment generation and poverty alleviation remained at the top of the agenda for the successive Governments in the country. The conference regrets to state that no worth while & sincere efforts were made by the rulling class to confront the twin problems. The Govt. of India launched the LPG & disinvestment policy in July 2001 admittedly under the dictates of the WB/IMF and various international monetary agencies. The Govt. of India introduced New Eco policy (NEP) & NLP. The Govt. painted a rosy picture of Indian economy on the application of NEP & NIP. The conference states that BMS contested the claims made by the Govt. & demanded thread bare debate on NEP/NIP and its import on the Indian economy. The Govt. of India however proceeded on the pre deter main LPG prescription. The montek Singh Ahluwalia committee report on "Employment oppunity, the Geeta Krishna committee report n expenditure Reform. The Rakesh Mohan committee report - on privatization, the planning commission sub committee report on employment generation and the export opinion on Foreign investment and employment growth, everybody supported the Govt. s. views and spoke aborts the unpward looking economy, employment generation. Flurry of activity on industrial sphere. More production, more income in the hands of the labour and common man. More demand for goods and services, more industrialization and host of there positive feature of the emerging Indian economy.

The conference noted that at the end of 14 years from the launch of LPG & Disinvestment policy the picture is economy to the claims made by the Govt. s and the advocates of the

economic reformers. The economy has moved form bad to worse. The organised sector employment dwindled. The shut down, clousres and law offs in big industry and establishments rendered lacs of workers jobless. The economy reformers led to voluntary separation of jobs, compulsory retirement scheme displacement and mobility and out sourcing of jobs. In order to survive the competition. The industries moved towards technology oriented work culture with substaincial reduction in the existing work force. The employment opportunities in the Govt. s establishment. The public and private sector almost dried up. The vicious circle is - no jobs no income less demand less production. Closure and shut downs of industrial units set in, to the great disadvantage of the National economy - the labour - the common man. Although the UPA Govt. s has introduce the bill in the parliament on Nation Rural Employment Goaratee scheme (NREGS) it is in truncated form. It does not speak about offering jobs to those below poverty line including the urban poor and the woman. The apparent inability of the Govt. s to provide huge funds to run the scheme have put question mark on actual implementation of the scheme.

The conference notes that the sum total of economy reforms resulted in the growth rate of employment declaning from 2.27% p.a. during the year 1983 -2000 (NSS). According to the central static cal Organization (CSO) the total employment in the countries organize sector declined by the annual compounded rate of 0.08% from 273.75 lac in 1993 -1994 to 272.06 on 2001-2002. Although agricultural sector registered a marginal growth in employees every other sector public, private, manufacturing, construction, financial, real estate-registered decline in the volume of existing employment and generation of employment.

The conference is of the considered view that the LPG and Disinvestment policy in the present from has failed to put the National economy on higher pedestal as claimed nay, the economy has moved from bad to worse in the last 14 years.

The conference demand on the Govt. of order to review the Parliament eco policy, hold round table conference of all economic interests and evolve our own model of development based on our ethos, cultural value, tradition and the requirements of the society. This conference insists that our economy system should be such as will enable every member of the society to fulfill has natural needs. This conference seeks right to work to every job seekers.

Thus conference calls upon the workers to undertake educative campaigns and to enlist the support of labour and common man for securing rights to work and welfare of the society.

PROPOSED BY: SECONDED BY:

Draft Resolution-4

SETTING UP 6th PAY COMMISSION FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

The Central Executive Commitee of BMS in its meeting at Raipur on 20th & 21th February 2005 in its resolution demanded immediate setting up of 6thPay Commission for Central Government Employees if not the long pending for permanent Bi-partite wage megotiating machinery by the Government.

During the pre-budget discussion with Finance Minister of India, the Bharatiya Mazdoor sangh (BMS) inter alia other TUpartners reiterated that the Government should now constitute the 6th Central Pay Commissin for Central Government employees as the revision of wages of Central Government employees periodically after ten years, as now become a common pgenmena. The 5th Central Pay Commission gas also recommended as under:

Quote :

Recommendation No. 171.72:

In case for any reason Government finds itself unable to set up a permanent pay body, it should at least concede the right of Central Government employees to have complete pay revision once in 10 years. This would mean that if the date of implementation of fifth Pay Commission is 1.1.6 the date of implementation of the SiXth Pay Commission should be pre-determined as 1.1.2006 irrespective of when the next Pay Commission is actually appointed. However,the Goverment should also take mote of the fact that it generally tades a Pay Commission a period of about three years to complete its deliberations and therefore, the next Pay Commission sgould be appointed latest by 1.1.2003, so that its report becomes available by 1.1.2006.

The 5th Central Pay Commision gas recommended setting up of Premanent pay body to review the pay and allowances of Government employees, preiodically. This is the view of BMS since its inception that there should be Permanent Bi-partite Wage Negotiating Machinery for Government Employees, but this has not been conceded by the Government so far. The recommendation of 5th Central Pay Commission vindicates the demand of BMS. If the Government for any reason could not set up this Permanent Pay Body, it should immediately announce settintg up of 6th Pay commission and enable it to submet its report well before 1.1.2006, the day from which next pay-revision is due for Central Government employees. To speed up the recommendation of the next pay revision mechanism, the Government should done away with the

aspect of Administrative Refoums as was looked into by the previous pay commissions, as the UPA Government has committed in its CMP to set up a Second Administrative Reforms Commission. This would enable timely revision of pay and allowances of Central Government employees since 1.1.2006.

PROPOSED BY: SECONDED BY:

Draft Resolution-5

B.M.S. demand for scrapping of new Patent Act.

The 14th National Triennial Conference of B.M.S. demands the Central Govt. to withdraw forth with the new Patent Act passed in March 2005. If the membership in W.T.O. and previous agreement come in the way in doing so, Govt of India should withdraw its membership and take initiative to form a new W.T.O. of the developing countries.

The new Patent Act allows the global patent for a period of 20 years. The British regime legislated an identical Act in India in 1911, which continued till 1970. During that period medicines were sold at abnormally high price. Therefore Govt. of India brought in its own legislation keeping in view the needs of the poor, as a result of which medicines have been available at 10% of prices in India, compared to world prices.

As Indian Companies have 1% patent only, the cost of medicines and the enormous profits of pharmacentical Companies amounting crores of rupees will go to foreign countries. India will be looted. The Monopoly and loot by foreign countries will continue for 20 years. Thereafter also it will be impossible for any body to get new patent since none will remain in competition. Besides this, according to experts, 15,000 out of

26,000 Pharmacentical Companies would have pull down their shutters in immediate future.

When prices rise, it would be difficult for retail traders to invest and as such they would be constrained to close the shops on large scale. Making use of article 31(b) of TRIPS agreement, India would have got a golden opportunity to sell products. But in the law no provision to that Effect is made in the powers of patent controller, whereas many other countries have made such provision. No thought has been given to provide for issues relating to public health and welfare-oriented indigenous companies in the law. In the old Law there was a provision for "objection before patent", which has been now changed as" Objection after patent" thereby rendering it ridiculous.

The present Law consists of many provisions detrimental to the nation and having disastrous effect on living of the poor and rendering them the slaves of foreign capital. This Conference severly condemns this Legislation. By supporting the new Patent regime, the double-tongued leftist parties have betrayed the poor people and worker. Political leadership and beaurocracy of the country has been bought by the foreign pharma companies. That is why the Act, harmful to the nation, has stood passed.

Therefore this conference calls upon the crores of poor people and workder to get prepared for battle in streets rather than leaving it to parliament.

The 14th Conference of B.M.S. directs the B.M.S. activists to consolidate the voice of people and save nation from clutches of foreigners, by bringing about unity of labour and farmers and by undertaking massive campaign of mass contact and mass awakening.

PROPOSED BY: SECONDED BY:

यह श्रमिकों की धरती है

यह श्रमिकों की धरती है, यहां नीति है, संस्कृति है।
यह सेतु–हिमाचल वसुधा, प्रिय भारत मां अपनी है।।

मेहनत से हम दुनिया में, उन्नति की ओर चले हैं।
चरणों में निज जननी के, अब जीवन पुष्प चढ़े हैं।।
अब संभव नहीं है रूकना, दिन बीत गया झुकने का।
बने हैं मन में ठानी, अब साथ–साथ चलने का।।

कण–कण भी इस मिट्टी के, हर बूंद बूंद सरिता के।
सदियों से हमें सुनाते, यहां बीज मानवता के।।
हम देश द्रोह नहीं जाने, विग्रह की नीति नहीं मानें।
हम कामगार भारत के, बस देश प्रेम पहचानें।।

गुरुद्वारों या मन्दिर में, मस्जिद या गिरजाघर में।
ईश्वर से मांग रहे हैं, सुख शांति संसारों में।।
हम पूजक हैं शक्ति के, संहारक दानवता के।
जो हम से टकरा जाता, हो जाते टुकड़े उसके।।

हम निर्माता बेरूल के, अजन्ता व ताजमहल के।
सांची के स्तूप बताते, वैभव दिन जगजननी के।।
चट्टानों को तोड़ा है, पर्वत को भी फोड़ा है।
सागर के तूफानों को, इन हाथों से मोड़ा है।।

दर्श विश्वकर्मा हैं, उन राहों पर चलना है।
मजदूर संघ भारत का अब शक्तिशाली करना है।।
दिन दूर नहीं वैभव के, गर राह चलें सब मिलके।
कह दो पुकार कर सारे, हम सुपुत्र भारत मां के।।

मुद्रण : बाल भारती, 9811613086